सत्यमेव जयते

# उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष, 2015 के प्रथम सत्र में

# डॉ0 कृष्ण कान्त पाल

## माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

# अभिभाषण

देहरादून, बुधवार, 11 मार्च, 2015 (फाल्गुन 20, शक सम्वत्, 1936)

**उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण**

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष, 2015 में विधान सभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ और देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप के माध्यम से, मैं प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि की भी कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेंगे ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम नया आयाम स्थापित कर सकें।

(1) **मेरी सरकार ने वर्ष 2013 की आपदा से ग्रस्त व्यवसायिक इकाईयों, दुकानों तथा अन्य** मदों को भी आपदा राहत में सम्मिलित करते हुए राहत की दरों में कई गुणा वृद्धि की है।

- **मेरी सरकार** ने वर्ष 2013 में भीषण प्राकृतिक आपदा के उपरान्त अत्यन्त कम समय में सभी सड़कों, पेयजल योजनाओं एवं विद्युत लाईनों आदि को सुचारू करते हुए चार धाम यात्रा को पुनः व्यवस्थित किया है और लगभग चार हजार गाँवों/बसासतों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की है।
- आपदा से क्षतिग्रस्त समस्त पेयजल योजनायें सुचारू की जा चुकी हैं।
- आपदा से राज्य के बाहर के मृत/लापता व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा चुके हैं तथा उनके परिवारों को राहत राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
- आपदा के उपरान्त पुनर्निर्माण कार्यों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (P.M.U.) जिसे विश्व बैंक व एशियन विकास बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण/सहायता से आच्छादित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन को समयबद्ध परियोजनाओं के रूप में सम्पादनार्थ स्थापित की गयी है।
- **मेरी सरकार** प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए आवासों को विश्व बैंक सहायतित आवासीय योजना के अन्तर्गत लगभग ढाई हजार परिवारों के लिए नये घरों का निर्माण कर रही है। इन सभी परिवारों के घर बन जाने तक उन्हें लगभग तीन हजार रुपये प्रति माह की दर से किराया अनुमन्य किया जा रहा है।

- स्थानीय स्तर पर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को त्वरित गति से संपादित करने की दृष्टि से परगना स्तर पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (P.I.U.) गठित की गयी है। पी0आई0यू0 द्वारा बाढ़ नियंत्रण, सम्पर्क मार्ग तथा अन्य अवस्थापनाओं की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं पर स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया गया एवं क्रियान्वयन किया गया।
- भविष्य में आपदाओं के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया अथवा प्रतिवादन की दृष्टि से राज्य में स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स (SDRF) का गठन किया गया। SDRF द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को सुनियोजित ढंग से किये जाने की दृष्टि से राज्य आपदा प्रबन्धन योजना (SDMP) का गठन किया जा चुका है, जिसमें सभी विभागों/संगठनों के दायित्वों को चिन्हित किया गया है तथा उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ किये जाने की दृष्टि से विभिन्न उपकरणों की स्थापना का कार्य विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक सहायतित परियोजना के अन्तर्गत गठित पी0एम0यू0 द्वारा किया जा रहा है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में 25 डी0एस0पी0टी0 फोन स्थापित किये गये हैं।
- मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाये जाने के उद्देश्य से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत सरकार के सहयोग से डॉप्लर वैदर रडार, ऑटोमेटिक वैदर स्टेशन (AWS) तथा ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना का कार्य विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक सहायतित परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जा रहा है।
- वर्ष 2013 की आपदा में राज्य के सभी मृतक व्यक्तियों के परिवारों को इस वर्ष रुपया दो लाख की अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य की गयी है। इस प्रकार कुल रुपया सात लाख की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में अनुमन्य करायी गयी है।

**(2) मेरी सरकार वाणिज्य कर में पारदर्शिता एवं क्षमता बढ़ाने हेतु कम्प्यूटराइजेशन करते** हुए ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिटर्न, ई–पेमेन्ट, ई–रिफण्ड, ऑनलाईन वाहन पंजीयन, ई–ट्रिपशीट की सुविधा, ई0डी0सी0आर0, हेल्पडेस्क एवं एस0एम0एस0 सर्विसेज आदि सुविधाएं प्रदान कर रही है। विभागीय कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत फार्म–सी एवं फार्म–11 ऑनलाईन डाउनलोड

किये जाने की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।

- राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में रुपया पाँच सौ करोड़ का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता के रूप में लगभग छः हजार युवक स्वरोजगार पोषित हैं और राज्य के चँहुमुखी विकास में राष्ट्रीय बचत योजनाओं में अधिकाधिक विनियोजन करवाकर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है।

- **मेरी सरकार** ने सोसायटी पंजीकरण, फर्म पंजीकरण, चिट्स पंजीकरण ऐक्ट, पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी समस्त जानकारी तथा फीस सम्बन्धी सूचनायें तथा आवेदन–पत्र फार्म इत्यादि आम सामान्य जन के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

(3) **सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आगामी वित्त वर्ष के प्रारम्भ से लागू** कर रही है। जिसके अन्तर्गत आयकर दाताओं एवं सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को छोडकर अन्य समस्त परिवारों के लिए चिन्हित बिमारियों के लिए रुपया पचास हजार वार्षिक नकद रहित स्वास्थ्य सेवा चिन्हित अस्पतालों में कराई जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों/यात्रा मार्गों पर प्रत्येक पचास कि0मी0 पर स्थित चिकित्सालयों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करते हुये चरणबद्ध रूप से ट्रोमा सेंटर की स्थापना कार्य प्रगति पर है।

- **मेरी सरकार** सभी चिकित्सा इकाईयों को सरकारी भवन में क्रियाशील करने हेतु कृत संकल्प है। इस हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

- **सरकार** एच0आई0वी0/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एच0आई0वी0/एड्स रोगियों को उपचार /औषधि प्रदान करने हेतु दून चिकित्सालय, देहरादून तथा सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल में एंटी रेट्रो वायरल **(ए0आर0टी)** उपचार की निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को उपचार/औषधि हेतु दूर न जाना पड़े इस हेतु राज्य के तेरह स्थानों में **लिंक ए0आर0टी0 केन्द्रों** की स्थापना कर क्रियाशील किया गया है। इस प्रकार अब राज्य के सभी जनपदों में एच0आई0वी0/एड्स रोगियों के उपचार हेतु औषधि उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में एड्स की व्यापकता दर 0.10 प्रतिशत है।

- कोटद्वार बेस चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किया जायेगा।

- गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय की स्थापना का कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण हो जायेगा। यह एक Super Speciality Hospital होगा, जिससे वृहत क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी।
- राज्य के जिला चिकित्सालयों/बेस चिकित्सालयों में दन्त शल्यक की आधुनिकतम् सुविधाएं जैसे– इम्पलान्ट, बोन ग्राफ्ट, लेजर सर्जरी, लिंग्वल ब्रेसेज आदि का सृजन किया जायेगा।
- **सरकार** चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अग्रणीय वन कर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे आम व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

**(4) मेरी सरकार पंचायत भवन निर्माण, राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान,** क्षमता विकास त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, क्षेत्र पंचायत विकास निधि तथा पंचायत सशक्तिकरण एवं जबावदेही प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन कर रही है।

- **सरकार** राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ई–पंचायत, केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पर्याप्त सकारात्मक कार्य सम्पादित कर रही है।
- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को और अधिक सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का सुचारू रूप में संचालित कर रही है, जिससे राज्य के अधिकतर व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
- खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि, सहभागी जलागम विकास, आजीविका वित्तपोषण, सहभागी जलागम विकास तथा आजीविका वित्त पोषण का संचालन सुचारू रूप से कर रही है।
- उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछडा क्षेत्र विकास निधि से सीमान्त एवं पिछड़े विकास खण्डों में स्थानीय आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं और विकास सम्बन्धी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा ऐसी नाजुक कड़ियों (Gap filling) को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रही हैं।
- सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0) के अन्तर्गत चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिह नगर तथा पिथौरागढ़ के 09 विकासखण्ड (क्रमशः जोशीमठ, लोहाघाट, चम्पावत, भटवाड़ी, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछिना, मूनाकोट) में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0) संचालित कर रही है।

- "मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना" से बी0पी0एल0 परिवारों के शिल्पकारों को कौशल वृद्धि, शिल्प डिजाईनिंग प्रशिक्षण देकर उद्यमिता विकास से जोड़ते हुये आजीविकोपार्जन में वृद्धि करने तथा शिल्प उत्पादों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

(5) **भारतीय संविधान में उपबन्धित अनुसूचित जनजातियों के हितों की विशेष रूप से** संरक्षित करने के दृष्टिगत सरकार अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है।

- समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इस क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व केन्द्रों का संचालन, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण, आदिम जनजातियों का विकास, एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं की स्थापना, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आर्थिक सहायता, जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना, अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की पुत्री के विवाह तथा बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना, आवर्तक अनुदान पर संचालित प्रा0 पाठशालाओं को अनुदान–सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान, गौरा देवी कन्याधन योजना, अटल आवास योजना, जनजाति सलाहकार परिषद्, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, लैपटाप वितरण योजना संचालित कर रही है।
- **मेरी सरकार** सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए वचनबद्ध है और लगातार उनके हितों के लिए प्रयासरत है।
- अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाना तथा अल्पसंख्यक समुदाय में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाने, छात्रवृत्ति योजनायें, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में (एम0एस0 डी0पी0) मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट योजना, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लाभान्वित करने, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण,

अनुदान एवं मार्जिन मनी की सुविधा, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, अल्पसंख्यक शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल वृद्धि योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने, शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मदरसों में दीनी तालीम के अलावा आधुनिक विषयों की शिक्षा यथा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि के प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों को मानदेय दिए जाने, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं में स्कूल छोड़ देने (ड्रॉप आउट) की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण के माध्यम से शिक्षा प्रोत्साहन दे रही है।

(6) **मेरी सरकार (जन्म से छः वर्ष) के कुपोषण स्तर को कम करने, स्कूल पूर्व शिक्षा से** जोड़ने तथा महिलाओं, किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधाऐं उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाने हेतु प्रयासरत है। बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों हेतु मेरी सरकार विभिन्न योजनायें संचालित कर रही है।

कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने हेतु मेरी सरकार ने नन्दा देवी कन्या योजना ''हमारी कन्या हमारा अभिमान'' संचालित की है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में वर्तमान में जन्मी प्रत्येक परिवार की दो कन्याओं को राज्य सरकार द्वारा ₹ 15000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। किशोरियों के स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल उन्नयन पर केन्द्रित सबला योजना हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली एवं नैनीताल में लागू है तथा शेष जनपदों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है।

(7) **उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक दृष्टि से खेलों** के विकास के लिए अत्यन्त ही उपयोगी है।

- **सरकार** खेलों के विकास, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं खेल संस्कृति विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- **मेरी सरकार** प्रान्तीय रक्षक दल के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्ध है जवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से वर्तमान में तीन सौ पचास रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता स्वीकृत किया है।

(8) **मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणीय कार्य कर रही है। इसमें** ई–शासन योजना, ई–डिस्ट्रिक्ट योजना महत्वपूर्ण है। विजन–2020 के अनुरूप राज्य में उत्कृष्ट वैज्ञानिक मानव संसाधन विकसित करने हेतु विज्ञान धाम परियोजना अन्तर्गत क्षेत्रीय

विज्ञान केन्द्र का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। मेरी सरकार विज्ञान केन्द्र में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता द्वारा वैज्ञानिक MODELS स्थापित करा रही है, जो वैज्ञानिक, शिक्षा एवं पर्यटन हब बनेगा।

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से परिषद् कार्यालय में मीडिया सेन्टर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
- परिषद् द्वारा राज्य के छात्र–छात्राओं हेतु इन्सपायर परियोजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक छात्रवृत्ति का लक्ष्य तैयार कर छात्रवृत्ति से छात्र–छात्राओं को लाभान्वित कराना प्रस्तावित है।
- अल्मोड़ा में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी समर्थकृत साधनों–सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र एवं भूमण्डलीय स्थापन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आधारभूत विकास, जल संसाधन प्रबन्धन, बर्फ/हिमनद अनुश्रवण, जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण, कृषि बागवानी, औषधीय पादपों से सम्बन्धित अध्ययनों एवं विकासात्मक संचार के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।
- सरकार यूसर्क के सहयोग से कुमाऊँ विश्वविद्यालय में 'सेन्टर फार क्लाइमेट चेंज' स्थापित कर राज्य के मौसम एवं प्राकृतिक घटनाक्रम का विषद् अध्ययन किया जा रहा है।
- गणित विषय को उत्तराखण्ड राज्य में रोचक बनाने एवं राज्य में गणित के विकास हेतु गणितीय विज्ञान के उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स इन मैथेमेटिकल साइन्सेज) की अल्मोड़ा में स्थापना की गयी है।
- उत्तराखण्ड केन्द्रित पाँच शोध परियोजनायें तैयार कर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं अन्य केन्द्रीय संस्थानों को वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गयी है। राज्य में आठ प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- जन चेतना एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने हेतु यूसर्क द्वारा विभिन्न विज्ञान सम्मत दिवसों यथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस सहित राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

- यूसर्क व्याख्यान माला के अन्तर्गत दस लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट व्याख्यान कराए गए हैं।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं (जरनल) में छः शोध पत्र प्रकाशित किये गए हैं।
- सरकार का उद्देश्य सामान्य जीवन में बीटी सेक्टर के महत्व को समझते हुए, उत्तराखण्ड का विजन, जैव–प्रौद्योगिकी का उपयोग अपनी जैव सम्पदा के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के साथ इसे द्रुततर आर्थिक समृद्धि हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का है।
- राज्य में जैव–प्रौद्योगिकी पार्क (Biotech Park) और उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना की शुरूआत की गई है।
- सरकार का ध्येय जैव–प्रौद्योगिकी, जैव सम्पदा के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के साथ जैव सम्पदा के दोहन व आर्थिक सम्पदा में परिवर्तित कर इसे राज्य के द्रुततर आर्थिक समृद्धि हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का है।
- सरकार ने आधुनिक उत्कृष्टता केन्द्र ;सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन माउटेन बायोलॉजी में पीएचडी प्रोग्राम प्रारम्भ करने का प्रायोजन, स्नातकोत्तर छात्रों/शोधकर्त्ताओं/शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता का विकास, ग्रीष्म/शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से आपसी समझौते किये हैं।
- सरकार ने जैव–प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जैव–प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने की योजना बनाई है। इस पार्क में जैव–प्रौद्योगिकी आधारित और अन्य औद्योगिकी इकाईयाँ स्थापित होंगी जिससे राज्य विकसित होने के साथ–साथ आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

(9) **मेरी सरकार ने आबकारी नीति में स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के** अवसर उपलब्ध कराते हुए मद्य निषेध नीति भी कारगर रूप से लागू की है।

(10) **मेरी सरकार ने राज्य भाषा हिन्दी, उर्दू और पंजाबी भाषा के प्रचार–प्रसार, संबर्द्धन** संरक्षण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उर्दू अकादमी तथा पंजाबी अकादमी की स्थापना की जा चुकी है।

**(11) मेरी सरकार सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करते हुए कृषि को सिंचित किए जाने** की कार्यवाही कर रही है। लघु सिंचाई के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य यथा गूलों, सिंचाई हौज, हाईड्रम नलकूप, बोरिंग/पम्प सेट, आर्टीजन कूप आदि का निर्माण कर सिंचन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

**(12) मेरी सरकार ने जनता की सुविधा के दृष्टिगत प्रशासनिक इकाईयों का विकेन्द्रीकरण** कर छोटी प्रशासनिक इकाईयों यथा तहसीलों और उप तहसीलों का निर्माण किया है।

- मेरी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में गैर वन नॉन जेड–ए भूमि में से भूमिहीनों, बी0पी0एल0 परिवारों एवं आपदा प्रभावित परिवारों को आवास के साथ भूमिहीन पशुपालकों को भी आवास स्थल के लिए व पशुशाला प्रयोग के लिए 180 वर्ग गज भूमि का आवंटन एक रुपया नजराना व मालगुजारी के बीस गुना की दर से वार्षिक किराये के रूप में शुल्क वसूल कर भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कर रही है।
- सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों का प्रमाण–पत्र, दैवीय आपदा व आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का विवरण वितरण, खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रति भू–चित्र व खसरे प्रति, किसान बही आदि उपलब्ध कराये जाने वाले सेवाओं में समय सीमा के भीतर उपलब्ध करा रही है।
- राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना की ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाण–पत्रों एवं अन्य नागरिक सेवाओं को उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कॉमन सर्विस केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान कर रही है।

**(13) मेरी सरकार ने उद्यान कार्ड वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया है। रोपण सामग्री** का उत्पादन, पर्याप्त मात्रा में किया गया है, मौनपालन योजना सुचारू रूप से किया गया है, घेरबाड़ योजना के लिए राज सहायता प्रदान की है, फसल बीमा योजना में कृषकों की भागीदारी, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन, नेशनल वैजिटेबिल इनिशिएटिव योजना का संचालन किया है।

**(14) मेरी सरकार रेशम विकास, चाय विकास तथा हर्बल विकास के क्षेत्र में सराहनीय** प्रयास कर रही है।

(15) **मेरी सरकार** ने योजना संरचना तथा अनुश्रवण का कार्य प्राथमिकता से करते हुए अब तक बारह परियोजनाओं का अनुश्रवण प्रारम्भ किया है।

(16) **राज्य में कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाडी क्षेत्र सम्मिलित हैं।** जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा, जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

- मेरी सरकार 1100 बस्तियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित करने, 1453 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन, 42 मिनी नलकूप, 29 गहरे नलकूप, 892 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्वार/सुदृढ़ीकरण किये जाने, चारधाम यात्रा मार्गों में पेयजल व्यवस्था यथावत् रखते हुये इनका रख–रखाव किये जाने, 30 नगरीय पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्वार/सुदृढ़ीकरण कार्य एवं 12 नगरीय पेयजल योजनाओं के नये कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता के अन्तर्गत 99926 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

- मेरी सरकार भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु कार्य प्रगति पर है।

- पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु लगभग रुपया अट्ठारह करोड़ एवं केन्द्र पोषित गंगा कार्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना अतिरिक्त में सम्मिलित उत्तराखण्ड के दस नगरों एवं राष्ट्रीय गंगा बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत रुपया तीस करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

(17) **वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर 101.64 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक** स्तर पर 93.53 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर 86.62 प्रतिशत है। मेरी सरकार उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर शत प्रतिशत करने हेतु कार्यवाही कर रही है तथा लड़कियों एवं सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन दर बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठा रही है। लड़कियों को निःशुल्क साईकिल/एफ0डी0 योजना से उनका उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन प्रतिशत भी बढ़ रहा है जो शुभ संकेत है। सरकार पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितयों के दृष्टिगत

विद्यालयों की स्थापना, उच्चीकरण प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी विषय एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता एवं शिक्षण संस्थाओं के पर्याप्त विनियमन, नियंत्रण व अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

- संस्कृत शिक्षा के उन्नयन एवं विकास को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार द्वारा संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
- संस्कृत शिक्षा एवं भाषा को बढ़ावा देने संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विनियम के गठन की कार्यवाही गतिमान है। मेधावी छात्रों हेतु योग्यता छात्रवृत्ति एवं महाकवि कालीदास छात्रवृत्ति प्रस्तावित है।
- संस्कृत के उन्नयन के लिए गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
- माँ नंदा देवी राजजात के पावन अवसर पर मेरी सरकार द्वारा 'नन्दा राजजात संस्कृतपद्यपुष्पांजलिः' नामक पुस्तक का प्रकाशन एवं सी0डी0 का निर्माण किया गया।
- **मेरी सरकार** द्वारा वर्तमान समय में पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं उपयोगिता, संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु संस्कृत नाट्य प्रतियोगिता, संस्कृत समूहगान, संस्कृत नृत्य, संस्कृत वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं श्लोकाच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि प्रदान कर रही है।
- **मेरी सरकार ने** राज्य में 15 नये राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना की है।
- राज्य के 17 स्थानों जोशीमठ, चोपता, पिपली, चिन्यालीसौड, पाबौ, पौड़ी, बाडेछीना, जैंती, भीमताल, बरम, बांसबगड, बेरीनाग, बछेलीखाल, चम्पावत, कपकोट, काण्डीखाल, बांस में समन्वयक की तैनाती करते हुये संस्थान को मूल घोषित स्थान से संचालित किया है। विकासनगर में महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

**(18) विधि–सम्मत हित संरक्षण के साथ ही त्वरित औद्योगिक विकास के लिये मेरी सरकार** सदैव प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य में यथा–सम्भव औद्योगिक शान्ति का वातावरण रहे व प्रदेश के उद्योगों में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाये रखने की ओर समुचित ध्यान देने के साथ ही समाज के अपेक्षाकृत निर्बल वर्ग के श्रमिकों के हित सम्वर्द्धन के प्रयास भी जारी रहें।

- बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।
- **मेरी सरकार** श्रमिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा कराये जाने की कार्यवाही कर रही है।

**(19) समाज में सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, एकता एवं अखण्डता को अक्षुण** बनाये रखने में मेरी सरकार सफल रही है।

- **सरकार** राज्य पुलिस कार्मिकों के कल्याणार्थ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य में आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य में "स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स" की छः वाहिनियों के गठन का प्रस्ताव है जिसके सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्यालय सहित चार वाहिनियों का गठन किया जा चुका है। दैवीय आपदा से निपटने में आपदा प्रभावित जनपदों में आपदा राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादन हेतु प्रभावी पुलिस संचार व्यवस्था स्थापित कर सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सेटेलाईट फोन के माध्यम से भी संचार व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी।

**(20) प्रदेश में अवैध खनन रोकने की दिशा में गृह विभाग के अन्तर्गत "अवैध खनन** निरोधक सतर्कता इकाई" का गठन किया गया है। प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में देहरादून व हरिद्वार शहर की यातायात व्यवस्था तथा स्ट्रीट क्राईम पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक नये प्रयोग के रूप में उत्तराखण्ड सिटी पैट्रोल का गठन किया गया है। भविष्य में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर एवं ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर शहर में भी सिटी पैट्रोल यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित है। सिटी पैट्रोल द्वारा सुदृढ़ एवं प्रभावी ढ़ग से यातायात के नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के तहत राज्य में प्रलेख, नारकोटिक्स, भौतिकी, प्राक्षेपिकी, सीरोलॉजी, बायोलॉजी, डी0एन0ए0 एवं विष व रसायन अनुभाग क्रियाशील है।

**(21) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अन्तर्गत** धान, गेहूँ एवं कदन्न धानों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। NFSM धान के अन्तर्गत पाँच जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर, NFSM गेहूँ के अन्तर्गत नौ जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधमसिंह

नगर तथा NFSM कदन्न धान्य के अन्तर्गत चार जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा तथा NFSM दाल (समस्त जनपद, ऊधमसिह नगर को छोड़कर) चयनित हैं।

- भारत सरकार की परिवर्तित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत विभाग की कई पुरानी योजनाओं के नाम में परिवर्तन करते हुए नई योजना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (NMAET) से प्रारम्भ की गई। इस नई योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों, विशेष रूप से आत्मा परियोजना का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक प्रभावशाली बनाना है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (NMAET) के निम्न घटक हैं :
- सरकार किसान के द्वार की रणनीति के अन्तर्गत खरीफ एवं रबी में बुआई से पूर्व कृषि महोत्सवों का आयोजन कराया जा रहा है।
- कृषकों को प्राकृतिक आपदा तथा फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- फार्मस पोर्टल के अन्तर्गत लगभग दो लाख किसान पंजीकृत हैं जिन्हें समय–समय पर कृषि से सम्बन्धित सलाह मोबाइल फोन SMS के माध्यम से भेजी जाती हैं। SMS द्वारा 4,98,970 किसान लाभान्वित हुए हैं।
- प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने हेतु किसान पेंशन योजना लागू की गई है।
- कृषि भूमि को जंगली जानवरों से बचाने हेतु कृषि भूमि की घेरबाड़ की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है।
- **मेरी सरकार** ए0पी0एल0 योजना, बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय अन्न योजना का सुचारू रूप से संचालन करते हुए जनता से उसके अधीन मिलने वाले लाभों को अनुमन्य करा रही है।
- **मेरी सरकार** ने आम जनता को चीनी और मिट्टी तेल उपलब्ध कराते हुए गेहूँ और धान खरीद का लक्ष्य पूर्ण किया है। इसी क्रम में व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से राज्य में माह अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक 5072 छापे मारे गये जिसके अन्तर्गत 16 एफ0 आई0 आर0, 10 गिरफ्तारी, 19 निलम्बित लाइसेन्स, 10 निरस्त लाइसेन्स तथा जब्त प्रतिभूति ₹ 155380.00 एवं ₹ 128500.00 अर्थदण्ड वसूला गया है।

- गेहूँ खरीद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन सत्र 2014–2015 में राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं एवं सहकारिता विभाग द्वारा 889.245 मी0टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 504.800 मी0टन कुल 1394.045 मी0टन गेहूँ का क्रय किया गया है। क्रय की गयी मात्रा में से 889.245 मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेटपूल में तथा 504.800 मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया गया है।
- धान खरीद योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक 932.440 मी0टन धान कॉमन तथा 184.720 मी0टन धान ग्रेड–ए तथा सहकारिता विभाग द्वारा 1817.600 मी0टन धान कॉमन तथा 22.36 मी0टन धान ग्रेड–ए क्रय किया गया है।
- **सरकार** सही तौल व माप उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे आम नागरिकों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।
- **सरकार** नें उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर सही वस्तुएँ प्राप्त हो सकें।

**(22) जलागम प्रबन्ध योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं** वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। यह योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग से चलाई जा रही हैं, जिसमें ग्रामीणों तथा ग्राम स्तर संस्थाओं की क्षमता एवं कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक और प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आय के संसाधन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि एवं आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है।

**(23) कर के ढांचे का सरलीकरण करने के उद्देश्य से मार्गकर, अतिरिक्त कर (माल** वाहन) एवं अतिरिक्त कर (यात्री वाहन) भिन्न–भिन्न करों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एकल कर ''मोटर यान कर'' अधिरोपित किये जाने तथा निजी ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वाहनों से एक ही फार्मूले पर कर का आरोपण, पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में भार वांहनों पर समान दर पर कर का निर्धारण, स्कूल कैब वाहनों से कम दर पर कर का आरोपण की व्यवस्था है।

- रक्षाबन्धन के दिन उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली बहनों/महिलाओं को, दिवगंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को एक सहायक के साथ तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के समस्त उत्तराधिकारियों को, विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों (मा0 संसद सदस्य, मा0 विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य, 04 प्रतिशत एवं उससे अधिक विकलांगताग्रस्त विकलांगजन, मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों को, उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

**(24) राज्य में विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन,** पारेषण तथा वितरण अक्षमता अवस्थापना तंत्र में पर्याप्त वृद्धि सहित उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत तथा बेहतर सेवायें देनें हेतु सभी सम्भव कदम उठाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

- सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार के लिए सजग है। सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में शत प्रतिशत उपलब्धि के निकट है। अवशेष लगभग एक सौ गाँवों का विद्युतीकरण उरेडा से संयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्माणाधीन कुल अठ्ठारह लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत उरेडा को आवंटित किया गया है जिसकी पूर्ति हेतु महिला एवं बाल कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग आदि से समन्वय कर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा राज्य में चालू घराटों के उच्चीकरण हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। इस हेतु दरों के निर्धारण एवं चैनल पार्टनरस का चयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा घराटों के उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है।

**(25) विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गों को समृद्धशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊँचा** उठाने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है।

- मेरी सरकार सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत सहकारी बैंकों एवं समितियों के माध्यम से लगभग साठ लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण एवं माह नवम्बर, 2014 तक लगभग बीस लाख रुपये का मध्यकालीन ऋण वितरण किया जा चुका है।
- विभिन्न समितियों के माध्यम से उन्नतशील बीजों का वितरण, गेहूँ एवं धान खरीद एवं उर्वरक की आपूर्ति के साथ–साथ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पैंतालिस लाख रुपये का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया है।
- समस्त जिला सहकारी बैंकों में कम्प्यूटराईजेसन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

**(26) नगरीय क्षेत्रों में जनित नगरीय समस्याओं, अनियंत्रित उपनिवेशों की स्थापना,** अत्यधिक जन दबाव के कारण प्रतिस्थापित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं भावी विकास को नियोजित, पर्यावरण सम्मत दिशा प्रदान किये जाने के उददेश्य से नगरों की महायोजना तैयार की जा रही है।

- सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के दृष्टिगत गैरसैंण विकास परिषद् का गठन किया है। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में बीस एकड़ भूमि पर मसूरी ईको पार्क की स्थापना एवं आई0एस0बी0टी0 के समीप Aquarium-cum-hotel-convention बनाया जाना प्रस्तावित है।
- विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एकल आवासीय भवनों को रियायती दरों पर शमन कराने हेतु One time settlement योजना लागू की गई।
- ई0डब्लू0एस0 (Economic Weaker Section) आवासों के आवंटन हेतु नीति निर्धारित की गई।
- जनपद देहरादून में राजपुर रोड एवं मसूरी माल रोड की विद्युत लाईन को भूमिगत किया जाना एवं चकराता रोड की क्षतिग्रस्त इमारतों, भवनों एवं दुकानों के पुनर्विकास की कार्यवाही हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद देहरादून में ढाकपट्टी, तरला नागल एवं धोरणखास क्षेत्रों में विभिन्न आवासीय योजनायें प्रस्तावित हैं।

**(27) मेरी सरकार ने पुराने उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली को ध्वस्त कर नया उत्तराखण्ड** निवास बनाये जाने का निर्णय लिया है।

- वासी नवीं मुम्बई सेक्टर 30–ए में उत्तराखण्ड राज्य को आंवटित भूखण्ड पर राज्य अतिथि गृह एवं इम्पोरियम के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है।
- भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय सम्बन्धी निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(28) **मेरी सरकार** सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करती है, जिससे अधिकारी/कर्मचारी कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहें।

**(29) राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील है।** राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सरकार राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ कर रही है। राज्य की नई एम0एस0एम0ई0 नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने के लिये आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

- **पारदर्शिता एवं उद्यमियों की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 एवं उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (Entrepreneur Memorandom Part-I and Part-II) फाईल करने की ऑन लाइन व्यवस्था है।**
- **विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म, उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में अधिकतम ₹ 05 लाख एवं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹ 03 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।**
- **प्रदेश में माह नवम्बर, 2014 तक कुल 46352 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना हुई है, जिनमें ₹ 9343.075 करोड़ पूँजी निवेश हुआ है तथा 216062 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।**
- **भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (PMEGP) के अन्तर्गत प्रदेश के लिये वर्ष 2014–15 में ₹ 22.46 करोड़ मार्जिन मनी एवं 1800 अभ्यर्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 425 लाभार्थियों को ₹ 11.57 करोड़ मार्जिन मनी**

संवितरित की गई तथा इससे 1855 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस योजना की प्रगति में उत्तराखण्ड का स्थान सराहनीय प्रदर्शन करने वाले राज्य में रहा है। हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं पुनःनिर्माण, पुनर्वास एवं पूर्व में लिए गये ऋणों के समायोजन हेतु रुपया दो करोड़ अठ्ठावन लाख की सहायता अनुमोदित की गयी है।

- "हिमाद्रि एम्पोरियम" के माध्यम से राज्य के हस्तशिल्पियों तथा हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में राज्य पैवेलियन प्रति वर्ष स्थापित किया जा रहा है।
- नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), अहमदाबाद के साथ प्रदेश के पारम्परिक शिल्पों पर आधारित सोविनियर विकास की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में ऊनी, ताम्र, ऐपण एवं रिंगाल आदि पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर नवीन उत्पाद विकसित किये गये। साथ ही बुनकर एवं शिल्पियों के लिये तकनीकी ज्ञान एवं कौशल उन्नयन हेतु राज्य के 08 चयनित शिल्पियों को प्रशिक्षण के लिये नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) अहमदाबाद भेजा गया।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों के दृष्टिगत भूमि का चिन्हीकरण सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- मुख्यमंत्री घोषणानुरूप परम्परागत शिल्पों के पुनर्जीवीकरण, विकास एवं उन्नयन हेतु "हरिराम टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान" की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस संस्थान को परम्परागत शिल्पों के उन्नयन के लिये एक उत्कृष्ट स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। परम्परागत वाद्य यत्रों, यथाः ढोल–दमाऊ, दैनिक उपयोग की विशिष्ट वस्तुओं, धार्मिक आयोजनों आदि के अवसर पर उपयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों, कृषि यंत्रों आदि के निर्माण की विधियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण आदि पर भी कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तथा धारचूला में हैण्डलूम कलस्टर विकसित करते हुये प्रोसेसिंग डाईंग प्लाण्ट सेन्टर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।

- मेरी सरकार उत्तराखण्ड ऊन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय कर सभी भेड़ पालक परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है तथा मुख्यमंत्री कलस्टर योजना के तहत स्थानीय स्तर से क्रय की गयी ऊन की धुलाई, कताई बुनाई व खादी के वस्त्र तैयार किये जाते हैं जिसमें स्थानीय स्तर के कतकर, बुनकरों एवं महिलाओं को उनके घर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं और इसे बेहतर बनाने व अधिक से अधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।
- गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर दैवीय आपदा के दृष्टिगत खादी वस्त्रों पर छूट की धनराशि दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दी गयी है।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) के अन्तर्गत अपने ही गाँव में स्वरोजगार के दृष्टिगत रुपया पच्चीस लाख ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- शासन द्वारा टैक्सटाईल पॉलिसी की स्वीकृति के पश्चात् काशीपुर एवं जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
- कोंकर लि० के साथ ज्वाइंट वेचर स्थापित कर लॉजिस्टिक हब के अन्तर्गत पंतनगर एवं हरिद्वार में रेलवे यार्ड की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। पंतनगर में ज्वाइंट वेचर द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिस पर लगभग ₹ 150 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- सिडकुल के समस्त औद्योगिक आस्थानों में मुख्य मार्गों में प्रकाश व्यवस्था एवं बिजली की खपत कम करने हेतु एल०ई०डी० लाइटें प्रयोग के तौर पर लगाई गयी हैं।
- स्मार्ट सिटी कान्सेप्ट आई०आई०ई० हरिद्वार में प्रायोगिक तौर में क्रियान्वयन किया जा रहा है ।
- सीडा निदेशक मण्डल द्वारा सिडकुल के समस्त औद्योगिक आस्थानों के मास्टर प्लान आवश्यक संशोधन करते हुए स्वीकृत किये गये हैं। उद्योगों को विस्तारीकरण के फलस्वरूप मिलने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उप विधि/ विनियम में संशोधन किये गये। जिससे उद्योगों को विस्तारीकरण

हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें एफ0ए0आर0 एवं ग्राउन्ड कवरेज में वृद्धि की गई है तथा वृद्धि किए गये क्षेत्र का उद्यमी को वर्तमान दर से सिडकुल को भुगतान करना होगा। तद्नुसार संशोधित GIDCR 2012 प्रकाशित की गई।

- सिडकुल द्वारा औद्योगिक आस्थानों मे मूलभूत सुविधायें यथा सड़के, बिजली, CETP, नालियाँ, आवासीय सुविधा, होटल एवं व्यवसायिक केन्द्र, ESI चिकित्सालय, अग्निशमन केन्द्र एवं पुलिस चौकी इत्यादि उपलब्ध करायी जा रही है।
- औद्योगिक आस्थान पन्त नगर में कल्याणी नदी को चैनेलाईज कर लगभग 50 एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है। जिसमें सिटी पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

**(30) शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत 06 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषदें एवं 44** नगर पंचायतें हैं। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीति–नियमों एवं प्रक्रियाओं के निर्धारण के साथ–साथ स्थानीय नगर निकायों को आवश्यक सहयोग एवं अनुदान उपलब्ध कराते हुए स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का सम्यक् अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जाता है।

- **मेरी सरकार** ने भारत सरकार के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं यथा पेयजल सुदृढ़िकरण सड़कों और चौराहों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजना, सीवरेज योजना, आवास निर्माण योजना आदि को पूर्ण सक्षमता से चला रही है।

**(31) सरकार ने राज्य के समस्त बूथों के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावलियों का** प्रकाशन कर दिया है।

**(32) मेरी सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण वनावरण में वृद्धि कराई है। इस वर्ष कुल 16281** वृक्षारोपण किया है।

- वर्षा जल संरक्षण हेतु विभाग द्वारा "वर्षा जल संरक्षण योजना" प्रारम्भ की जा रही है जिसके अन्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण कार्य, जलाशय, टैंक, जलकुण्डो का निर्माण, तटबन्ध, जलस्रोतों का पुनरोद्धार आदि कार्य किये जाने है।
- वन्यजीवों जैसे सुअर, नीलगाय, हाथी तथा बन्दरों द्वारा कृषकों की खेती को प्रतिवर्ष नुकसान किया जाता है जिससे कृषकों द्वारा खेतो को बंजर छोड़ा जा रहा है। इस

दृष्टिकोण से "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजना" प्रारम्भ की जा रही है।

- प्रदेश में उन्नत चारे की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से चारागाह विकास योजना से प्रारम्भ की जा रही है जिसमें उन्नत किस्म की चाराघास, चारा प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
- "हल्द्वानी में एक चिड़ियाघर निर्माण" के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- प्रदेश में वानिकी कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के उद्देश्य से ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण योजना के अन्तर्गत कुल छः कम्पनियां कार्यरत हैं। इन कम्पनियों के द्वारा देहरादून, अल्मोडा, चमोली तथा पिथौरागढ़ जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ स्थलों में वनीकरण कार्य किये जा रहे हैं, जिससे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है।
- प्रदेश के वनों में प्रतिवर्ष ग्रामीण पशुओं द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से चराई की जाती है जिसका रियायती मूल्य लगभग रुपया तैंतीस करोड़ है। इसी प्रकार प्रदेश की ग्रामीण जनता द्वारा प्रतिवर्ष अप्रत्यक्ष रूप से औसतन दो सौ चौदह मिलियन टन जलौनी लकड़ी का वनों से चुगान किया जा रहा है जिसका कुल रियायती मूल्य लगभग ₹ 213.9 करोड़ है।

**(33) मेरी सरकार ने राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर/केन्द्रीय वित्त पोषित/वाह्य सहायतित** योजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत कुल 14,236 किमी0 मोटर मार्ग के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/सुधार तथा 1193 मोटर सेतु तथा 495 पैदल सेतु सहित कुल 1688 सेतुओं के निर्माण आदि पर कुल ₹ 10751.49 करोड़ का व्यय किया गया।

- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (यू0एस0आर0आई0पी0) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2014–15 के माह नवम्बर 2014 तक कुल 92 कि0मी0 का पुनर्निर्माण एवं सुधार करते हुए कुल ₹ 119.65 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया गया।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनेक गाँवों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया है।

- प्रदेश के राज्य मोटर मार्गों में यातायात को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक कार्य किये गये हैं जैसे–वर्तमान में निर्मित एक लेन के राज्य मोटर मार्गों का दो लेन में परिवर्तन, जनपद हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में रेलवे क्रासिंग पर ऊपरगामी सेतुओं का निर्माण, देहरादून शहर में फ्लाई ओवर का निर्माण, प्रदेश में निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का किया जाना आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

(34) **मेरी सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जैसे–चारे** की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक विकास खण्डों में चारा बैंकों की स्थापना की गयी है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रोत्साहन के रूप में कुक्कुट इकाईयों की स्थापना हेतु 50–50 कुक्कुट चूजे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11900 एस०सी०पी० तथा 3510 टी०एस०पी० कुक्कुट इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है ।
- राज्य में गाय एवं भैसों की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर क्षेत्रों तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य को विस्तारित किया गया है।
- पशुपालकों के पशुधन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पशुधन बीमा योजना चलायी जा रही है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर माइक्रो डेरी, बकरी पालन एवं कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा सहायतित एस्केड योजना से राज्य में पशुधन की सुरक्षा हेतु टीकाकरण कार्य किया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राज्य सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त अण्डा उत्पादन, ऊन उत्पादन एवं मांस उत्पादन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
- डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित की जा रही हैं।
- प्रदेश के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।

**मैनें अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा।** मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए। इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। साथ ही विधान सभा सत्र के दौरान अपने समय का अधिकाधिक उपयोग जन समस्याओं के समाधान एवं प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में अपनी विद्वता का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मैं सम्मानित सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

**जय हिन्द!**